भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2948
10.07.2019 को उत्तर देने के लिए

जीडीपी में सुधार

2948. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनएसएसओ के नवीनतम आंकड़ों में अनुसार वर्तमान जीडीपी विकास दर एवं रोजगार वृद्धि दर क्या है;

(ख विगत छह महीनों के दौरान जीडीपी में कम वृद्धि दर के क्या कारण हैं;

(ग) जीडीपी विकास दर में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित है; और

(घ) वर्तमान रोजगार वृद्धि दर के वर्तमान स्तर, जो कि पिछले बीस वर्षों में निम्नतम स्तर पर है, में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर और वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर तिमाही–वार जीडीपी की वृद्धि दरें तथा क्षेत्र-वार सकल मूल्य वर्धन वृद्धि दरें इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा प्रासंगिक सार अनुलग्नक पर हैं । वर्ष 2018-19 की अंतिम दो तिमाहियों में, कुछ क्षेत्रों, नामत: कृषि, वानिकी और मत्स्यन तथा विनिर्माण में सापेक्ष रूप से कम वृद्धि दर थी । वर्ष 2017-18 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कार्यबल भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैं:

डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में)	एलएफपीआर (प्रतिशत में)	यूआर (श्रम बल में) (प्रतिशत में)
34.7	36.9	6.1

(ग): भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न मंत्रालय और विभाग, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार के विभिन्न कार्यनीतिक कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित कर रहे हैं । सरकार ने अर्थव्यवस्था की सकल देशीय उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना, ईज आफ डूइंग बिजनेस में सुधार के उपायों, उज्ज्वल डिस्काम ऐश्योरेंस योजना (उदय) जैसी स्कीमों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र के उपायों सहित परिवहन क्षेत्र के लिए ठोस उपाय शामिल हैं । अन्य उपायों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में व्यापक सुधार तथा कपड़ा उद्योग के लिए विशेष पैकेज शामिल है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत व्यापार, बिजनेस तथा संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों को करने में आने वाली बाधाओं को कम करके विकास की गति में सुधार करने के लिए उद्दिष्ट है । सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से कृषकों की आय को प्रोत्साहन दे रही है । अंतरिम बजट 2019-20 में, सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार के लिये विभन्न आगतों (इनपुट) की खरीद हेतु, वित्तीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) प्रारंभ किया है ।

(घ): समावेशी विकास हासिल करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है । समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार बेहतर रोजगार अवसर के सृजन, सामाजिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है तथा जनसंख्या के सभी वर्गों को समिल्लित करने के लिए पानी, बिजली, सड़कें, साफ-सफाई और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है । जनांकिकी विभक्ति का लाभ उठाते हुए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना(पीएमईजीपी), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयु-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयुएलएम) जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करके सरकार अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान कर रही है । सरकार उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का विचार कर रही है । साथ ही, 10 मिलियन युवाओं को उनकी नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

*****

अनुलग्नक

तालिका: स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर (% में)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
5.5	**6.4**	**7.4**	**8.0**	**8.2**	**7.2**	**6.8**

तालिका 2: जीडीपी के त्रैमासिक अनुमान तथा स्थिर मूल्यों (2011-12) श्रृंखलाओं पर सकल मूल्य वर्धन वृद्धि दर (% में)

मद	**2018-19**			
	तिमाही 1	**तिमाही2**	**तिमाही3**	**तिमाही4**
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यन	5.1	4.9	2.8	-0.1
2. खनन और उत्खनन	0.4	-2.2	1.8	4.2
3. विनिर्माण	12.1	6.9	6.4	3.1
4. बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवांए	6.7	8.7	8.3	4.3
5. निर्माण	9.6	8.5	9.7	7.1
6. व्यापार, होटल, परिवहन संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	7.8	6.9	6.9	6.0
7. वित्तीय, स्थावर सम्पदा (रीयल एस्टेट) और व्यावसायिक सेवाएं	6.5	7.0	7.2	9.5
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	7.5	8.6	7.5	10.7
9. कुल जीवीए	**7.7**	**6.9**	**6.3**	**5.7**
10. जीडीपी	**8.0**	**7.0**	**6.6**	**5.8**

तिमाही-1: (अप्रैल-जून), तिमाही-2: (जुलाई-सितंबर), तिमाही-3: (अक्तूबर-दिसंबर), तिमाही-4: (जनवरी-मार्च)